

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 153]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 26, 2014/चैत्र 5, 1936

No. 153]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 26, 2014/CHAITRA 5, 1936

गृह मंत्रालय

(सी एस प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मार्च, 2014

**सा.का.नि. 210(अ).**—बन्दी प्रत्यावर्तन अधिनियम, 2003 (2003 का 49) की धारा 3 की उप-धारा 445 (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, दिनांक 27 सितम्बर, 2013 को क्रार का अनुसमर्थन करने के बाद एतद्वारा निदेश देती है कि उक्त अधिनियम के उपबंध तुर्की गणराज्य पर लागू होंगे तथा उस देश एवं भारत के बीच कैदियों के अंतरण के लिए भारत गणराज्य की सरकार एवं तुर्की गणराज्य की सरकार के बीच हुए क्रार के पाठ को अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

**दण्डित व्यक्तियों के अन्तरण के संबंध में भारत गणराज्य तथा तुर्की गणराज्य के बीच क्रार**

भारत-गणराज्य तथा तुर्की गणराज्य, जिन्हें इसमें इसके बाद संविदाकार देश कहा गया है;

दण्डित व्यक्तियों का उनके स्वयं के देशों में सामाजिक पुनर्वास सुगम बनाने की अभिलाषा से; और

यह मानते हुए कि यह उद्देश्य कोई दण्डित अपराध करने के परिणामस्वरूप दोषसिद्ध और दण्डित किए गए विदेशी नागरिकों को उनके स्वयं के समाज में अपनी सज़ा काटने का अवसर प्रदान करके पूरा किया जाना चाहिए;

निम्न प्रकार सहमत हो गई हैं :

**अनुच्छेद 1****परिभाषाएं**

इस क्ररार के प्रयोजन के लिए :

- (क) “निर्णय” से तात्पर्य न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के किसी ऐसे निर्णय अथवा आदेश से है जिसके तहत अन्तिम रूप से दण्ड दिया गया हो;
- (ख) “प्राप्तकर्ता देश” से तात्पर्य उस देश से है जिसको दण्डित व्यक्ति सज़ा अथवा बाकी की सज़ा काटने के प्रयोजन से अंतरित किया जा सकता हो अथवा अंतरित किया गया हो;
- (ग) “दण्ड” से तात्पर्य किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण द्वारा अपने दाण्डिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए निर्धारित समयावधि के लिए या आजीवन के लिए आजादी से वंचित रखे जाने का कोई अन्तिम दण्ड या उपाय है;
- (घ) “दण्डित व्यक्ति” से तात्पर्य किसी दाण्डिक न्यायालय, जिसमें संविदाकार देश में तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा स्थापित न्यायालय भी शामिल हैं, द्वारा पारित किसी निर्णय के तहत कारावास की सज़ा काट रहे व्यक्ति से है;
- (ङ) “अंतरणकर्ता देश” से तात्पर्य उस देश से है जिसमें उस व्यक्ति को दण्ड दिया गया हो, जिसे अंतरित किया जा सकता हो या जिसे अंतरित कर दिया गया हो।

**अनुच्छेद 2****सामान्य सिद्धांत**

1. इस क्ररार के प्रावधानों के अनुसार किसी संविदाकार देश के भू-भाग में दाण्डिक किसी व्यक्ति को उसे दी गई सज़ा काटने के लिए संविदाकार देश के भू-भाग में अंतरित किया जा सकता है ताकि वह उसे दी गई सज़ा काट सके। इस संबंध में, दण्डित व्यक्ति इस क्ररार के अन्तर्गत अंतरणकर्ता देश अथवा प्राप्तकर्ता देश से ऐसे अंतरण के लिए अपनी इच्छा व्यक्त कर सकता है।
2. अन्तरण का अनुरोध किसी दण्डित व्यक्ति द्वारा, जो किसी संविदाकार देश का नागरिक है, अथवा संविदाकार देशों के कानूनों के अनुसार उसके स्थान पर कार्य करने के लिए हकदार किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संविदाकार देश को और उक्त संविदाकार देश की सरकार द्वारा निर्धारित किए गए तरीके से आवेदन प्रस्तुत करके किया जा सकता है।

**अनुच्छेद 3****केन्द्रीय प्राधिकारी**

1. संविदाकार देशों की ओर से इस क्ररार के कार्यान्वयन के लिए प्रभारी केन्द्रीय प्राधिकारी निम्नलिखित हैं:  
 भारत गणराज्य के लिए : गृह मंत्रालय ;  
 तुर्की गणराज्य के लिए : न्याय मंत्रालय।
2. यदि कोई संविदाकार देश अपना सक्षम प्राधिकारी बदलता है तो वह दूसरे देश को सरकारी चैनलों के माध्यम से उक्त परिवर्तन के बारे में अधिसूचित करेगा।

**अनुच्छेद 4****अंतरण की शर्तें**

1. इस क्ररार के अंतर्गत किसी दण्डित व्यक्ति को निम्नलिखित शर्तों पर ही अन्तरित किया जा सकता है :  
 (क) वह व्यक्ति प्राप्तकर्ता देश का नागरिक हो,

- (ख) निर्णय अंतिम हो;
- (ग) अंतरणकर्ता देश में दण्डित व्यक्ति के विरुद्ध कोई दाण्डिक कार्यवाही जिसमें उसकी उपस्थिति अपेक्षित हो, लम्बित नहीं हो;
- (घ) अंतरण के अनुरोध की प्राप्ति के समय, दण्डित व्यक्ति द्वारा भोगी जाने वाली सज़ा की अवधि कम से कम छः माह बची हो अथवा वह आज़ीवन कारावास की सज़ा काट रहा हो;
- (ङ) दण्डित व्यक्ति को अंतरणकर्ता देश में जिन कृत्यों अथवा चूकों के लिए दण्ड दिया गया था, वे प्राप्तकर्ता देश में दण्डनीय अपराध हैं अथवा यदि उसके अपने भू-भाग में किए जाते तो दाण्डिक अपराध होते;
- (च) प्राप्तकर्ता देश में दण्डित व्यक्ति की हिरासत को अंतरित करने से अंतरणकर्ता देश की संप्रभुता, सुरक्षा अथवा किसी अन्य हित पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ता हो;
- (छ) यदि अंतरण के संबंध में दण्डित व्यक्ति द्वारा सहमति दी गई हो अथवा किसी भी संविदाकार देश के द्वारा दण्डित व्यक्ति की आयु अथवा शारीरिक या मानसिक स्थिति को ध्यान में रखकर जरूरी समझे जाने पर दण्डित व्यक्तियों के कानूनी प्रतिनिधि अथवा उस व्यक्ति की ओर से कार्य करने के लिए हकदार किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सहमति दी गई हो; और
- (ज) अंतरणकर्ता और प्राप्तकर्ता देश अंतरण के संबंध में सहमत हों।

2. आपवादिक मामलों में यदि दण्डित व्यक्ति द्वारा भोगे जा रहे दण्ड की शेष अवधि छः माह से कम हो तो भी अंतरणकर्ता और प्राप्तकर्ता देश अंतरण के संबंध में सहमत हो सकते हैं।

### अनुच्छेद 5

#### सूचना भेजने का दायित्व

(1) यदि दण्डित व्यक्ति ने अंतरणकर्ता देश को इस करार के तहत अन्तरित होने की इच्छा व्यक्त की हो तो, अंतरणकर्ता देश प्राप्तकर्ता देश को निम्नलिखित सूचना तथा दस्तावेज़ भेजेगा बशर्ते कि प्राप्तकर्ता या अंतरणकर्ता देश में से किसी के भी द्वारा पहले ऐसा कोई निर्णय न लिया गया हो कि वह अंतरण के लिए सहमत नहीं है:

- (क) दण्डित व्यक्ति का नाम एवं राष्ट्रियता, जन्म तिथि एवं जन्म स्थान तथा प्राप्तकर्ता देश में उसका पता, यदि कोई हो, और साथ ही उसके पासपोर्ट अथवा कोई अन्य वैयक्तिक पहचान संबंधी दस्तावेज़ों की प्रति तथा दण्डित व्यक्ति के अंगुलछाप, यथासंभव;
- (ख) उन तथ्यों का विवरण जिन पर दण्ड आधारित था;
- (ग) दण्ड की प्रकृति, समयावधि एवं प्रारंभ होने की तारीख;
- (घ) निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा कानून के उन संगत उपबंधों की एक प्रति जिनके अंतर्गत दण्डित व्यक्ति के खिलाफ दण्ड पारित किया गया है;
- (ङ) दण्डित व्यक्ति की कोई चिकित्सीय, सामाजिक अथवा अन्य कोई रिपोर्ट, जहां वह उसके आवेदन के निपटान अथवा उसकी परिरुद्धता की प्रकृति के निर्धारण के लिए प्रासंगिक हो;
- (च) कोई अन्य जानकारी जिसे अंतरणकर्ता देश विनिर्दिष्ट करे कि यह अंतरण की संभावना पर विचार करने के लिए जरूरी है और जिससे वह अपने कानून के अंतर्गत दण्डित व्यक्ति को अंतरण के सम्पूर्ण परिणामों की जानकारी देने में सक्षम होने के लिए जरूरी है;
- (छ) अंतरित किए जाने वाले दण्डित व्यक्ति अथवा अंतरणकर्ता देश के कानून के अनुसार उसकी ओर से कार्य करने के लिए अधिकृत किसी भी व्यक्ति अथवा दण्डित व्यक्ति के कानूनी प्रतिनिधि का अनुरोध;

- (ज) किसी विचारण पूर्व नजरबंदी, क्षमा या दण्ड प्रवर्तन के लिए संगत किसी अन्य तथ्य को शामिल करते हुए, एक विवरण पत्र जिसमें यह उल्लेख किया गया हो कि कितना दण्ड पूरा हो चुका है; और
- (झ) अपेक्षित सूचना भेजे जाने के बाद दण्डित व्यक्ति को अंतरण पर सहमति देते हुए अंतरणकर्ता देश की ओर से एक विवरण प्राप्तकर्ता देश को प्रदान किया जाएगा।

2. इस क्रार के अधीन किसी अनुरोध पर कोई भी निर्णय लिए जाने के प्रयोजन से प्राप्तकर्ता देश अंतरणकर्ता देश को निम्नलिखित जानकारी एवं दस्तावेज़ तभी भेजेगा जब प्राप्तकर्ता या अंतरणकर्ता देश ने पहले ही यह निश्चय कर लिया हो कि वह अंतरण से सहमत नहीं है:

- (क) एक विवरण अथवा दस्तावेज़ जो यह दर्शाता हो कि दण्डित व्यक्ति प्राप्तकर्ता देश का एक नागरिक है;
- (ख) प्राप्तकर्ता देश के संगत कानून की एक प्रति जिसमें यह प्रावधान किया गया हो कि ऐसे कृत्य अथवा चूकें शामिल हैं, जिनके कारण अंतरणकर्ता देश में दण्ड पारित किया गया है, प्राप्तकर्ता देश के कानून के अंतर्गत अपराध माने गए हैं अथवा यदि इसके भू-भाग में घटित होते तो दण्डित अपराध माने जाते;
- (ग) दण्डित व्यक्ति के अंतरण पर इस क्रार के अनुच्छेद 9 के पैराग्राफ 2 के प्रभाव का विवरण, यदि लागू हो, के सहित उसके अंतरण के बाद प्राप्तकर्ता देश में सज़ा की अवधि एवं प्रवर्तन संबंधी किसी कानून अथवा विनियम के प्रभाव का विवरण;
- (घ) दण्डित व्यक्ति के अंतरण को स्वीकार करने के लिए प्राप्तकर्ता देश की सहमति और दण्डित व्यक्ति की सज़ा के बाकी बचे हिस्से को शासित करने हेतु एक वचनबद्धता; और
- (ङ) कोई अन्य सूचना अथवा दस्तावेज़ जिसे अंतरणकर्ता देश आवश्यक समझे।

### अनुच्छेद 6

#### अनुरोध एवं जवाब

1. अंतरण के लिए अनुरोध लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाएगा और राजनयिक चैनलों के माध्यम से अंतरणकर्ता देश के केन्द्रीय प्राधिकारी द्वारा प्राप्तकर्ता देश के केन्द्रीय प्राधिकारी को सम्बोधित किया जाएगा। जवाब उन्हीं माध्यमों से संसूचित किए जाएंगे।
2. प्राप्तकर्ता देश शीघ्रतापूर्वक अंतरणकर्ता देश को अपने निर्णय के बारे में सूचित करेगा कि वह प्रार्थित अंतरण के लिए सहमत है अथवा नहीं।

### अनुच्छेद 7

#### सहमति और इसका सत्यापन

- (1) अंतरणकर्ता देश यह सुनिश्चित करेगा कि इस क्रार के अनुच्छेद 4 के पैरा 1 (छ) के अनुसार अंतरण के लिए सहमति देने के लिए अपेक्षित व्यक्ति, ऐसा स्वेच्छा से तथा इसके कानूनी परिणामों की पूरी जानकारी के साथ कर रहा है। इस प्रकार की सहमति देने की प्रक्रिया को अंतरणकर्ता देश के कानून द्वारा शासित होगी।
- (2) अंतरणकर्ता देश, प्राप्तकर्ता देश को किसी कॉन्स्यूल अथवा प्राप्तकर्ता देश के कानून के अनुसार नियुक्त अन्य अधिकारी के माध्यम से यह सत्यापित करने के लिए एक अवसर प्रदान करेगा कि सहमति, इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 में निर्धारित शर्तों के अनुसार प्रदान की गई है।

### अनुच्छेद 8

#### प्राप्तकर्ता देश के लिए अंतरण का प्रभाव

- (1) इस क्रार के अनुच्छेद 9 में निर्धारित शर्तों के अधीन, प्राप्तकर्ता देश के सक्षम प्राधिकारी किसी न्यायालय अथवा प्रशासनिक आदेश, जैसा भी इसके राष्ट्रीय कानून के तहत अपेक्षित होगा, के माध्यम से सज़ा का प्रवर्तन जारी रखेंगे।

(2) इस करार के अनुच्छेद 11 के प्रावधानों के अधीन, सज़ा का प्रवर्तन प्राप्तकर्ता देश के कानून द्वारा शासित किया जाएगा और कि सिर्फ वही देश समस्त समुचित निर्णय लेने के लिए सक्षम होगा।

### **अनुच्छेद 9**

#### **सज़ा का सतत प्रवर्तन**

(1) प्राप्तकर्ता देश, अंतरणकर्ता देश द्वारा यथा अभिनिर्धारित सज़ा की कानूनी प्रकृति एवं अवधि द्वारा आवद्ध होगा।

(2) यदि सज़ा की प्रकृति अथवा अवधि अथवा दोनों ही, प्राप्तकर्ता देश के कानून से असंगत हों, तो प्राप्तकर्ता देश अंतरणकर्ता देश की पूर्व सहमति से सज़ा को अपने स्वयं के कानून द्वारा, उसी प्रकार के अपराध के लिए निर्धारित दण्ड उपाय में रूपान्तरित कर सकेगा। जहां तक दण्ड अथवा उपाय की प्रकृति एवं अवधि का संबंध है, यह यथासंभव, अंतरणकर्ता देश के अधिनिर्णय द्वारा अधिरोपित सज़ा के अनुरूप होगा। तथापि, यह अपनी प्रकृति अथवा अवधि द्वारा, अंतरणकर्ता देश में अधिरोपित सज़ा में वृद्धि नहीं करेगा।

### **अनुच्छेद 10**

#### **अंतरणकर्ता देश के लिए सज़ा के समापन का प्रभाव**

जब प्राप्तकर्ता देश इस करार के अनुच्छेद 13 के पैराग्राफ 1 (क) के तहत अंतरणकर्ता देश को यह अधिसूचित करता है कि दण्ड पूरा हो गया है, तो ऐसी अधिसूचना अंतरणकर्ता देश में उस दण्ड को पूरा करने के संबंध में प्रभावी मानी जाएगी।

### **अनुच्छेद 11**

#### **निर्णय की समीक्षा और दण्ड की माफी, राजक्षमा अथवा लघुकरण**

- (1) केवल अंतरणकर्ता देश को ही निर्णय की पुनरीक्षा के लिए किसी आवेदन-पत्र पर निर्णय लेगा।
- (2) कोई भी संविदाकार देश अपने संविधान अथवा अन्य कानूनों के अनुरूप दण्ड की माफी, राजक्षमा प्रदान कर सकेगा अथवा दण्ड का लघुकरण कर सकेगा।

### **अनुच्छेद 12**

#### **दण्ड के प्रवर्तन की समाप्ति**

1. अंतरणकर्ता देश अपने भू-भाग के लिए गए किसी भी निर्णय जिसके द्वारा दण्ड अथवा इसके किसी हिस्से के प्रवर्तन का समापन आवश्यक हो गया हो, के बारे में तत्काल प्राप्तकर्ता देश को अधिसूचित करेगा।
2. जैसे ही अंतरणकर्ता देश द्वारा किसी भी ऐसे निर्णय अथवा उपाय की सूचना दी जाती है, जिसके परिणामस्वरूप दण्ड का प्रवर्तन समाप्त हो गया हो, तो प्राप्तकर्ता देश दण्ड या उसके भाग के प्रवर्तन को समाप्त कर देगा।

### **अनुच्छेद 13**

#### **दण्ड के प्रवर्तन संबंधी सूचना**

1. प्राप्तकर्ता देश अंतरणकर्ता देश को अधिसूचित करेगा :
  - (क) जब दण्ड का प्रवर्तन पूरा कर लिया गया हो; अथवा
  - (ख) यदि दण्ड का प्रवर्तन पूरा होने से पहले दण्डित व्यक्ति हिरासत से भाग जाता है, ऐसे मामलों में प्राप्तकर्ता देश दण्डित व्यक्ति की गिरफ्तारी के उपाय करेगा ताकि वह दण्ड का शेष भाग पूरा कर सके तथा उसे प्राप्तकर्ता देश के संगत कानून के अन्तर्गत जेल से भागने के अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सके।

2. यदि अंतरणकर्ता देश द्वारा अपेक्षित हो, तो प्राप्तकर्ता देश दण्ड के प्रवर्तन के संबंध में एक विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

### **अनुच्छेद 14**

#### **अभिवहन**

1. यदि कोई भी संविदाकार देश दण्डित व्यक्तियों के अंतरण के लिए किसी तीसरे देश के साथ कोई व्यवस्था करता है, तो दूसरा संविदाकार देश ऐसी व्यवस्था के अनुसरण में अपने भू-भाग से अंतरित किए जाने वाले दण्डित व्यक्तियों के अभिवहन को सुकर बनाने में सहयोग करेगा, सिवाय इसके कि वह निम्नलिखित स्थिति में अभिवहन से इन्कार कर सकता है:-

(क) यदि दण्डित व्यक्ति उसका अपना राष्ट्रिक हो; अथवा

(ख) अनुरोध से, संविदाकार देश की संप्रभुता, सुरक्षा, लोक व्यवस्था अथवा अन्य जरूरी हित का अतिक्रमण होता है।

2. ऐसे अंतरण का इच्छुक संविदाकार देश, दूसरे संविदाकार देश को ऐसे अभिवहन के बारे में अग्रिम नोटिस देगा।

### **अनुच्छेद 15**

#### **लागत**

अंतरणकर्ता देश के अनन्य भू-भाग में होने वाले व्यय को छोड़कर, इस करार को लागू करने में आने वाले सभी खर्चे प्राप्तकर्ता देश द्वारा वहन किए जाएंगे। तथापि, प्राप्तकर्ता देश, अंतरण में होने वाले सम्पूर्ण अथवा आंशिक खर्च की वसूली दण्डित व्यक्ति अथवा किसी अन्य संसाधन से प्राप्त कर सकता है।

### **अनुच्छेद 16**

#### **भाषा**

अनुरोध एवं सहायक दस्तावेज प्रत्येक संविदाकार देश की राजभाषा में होंगे और इसके साथ अंग्रेजी अनुवाद संलग्न होगा।

### **अनुच्छेद 17**

#### **लागू होने का दायरा**

यह करार, इसके प्रभावी होने की तारीख से पहले या बाद में लगाए गए दण्ड के प्रवर्तन पर लागू होगा।

### **अनुच्छेद 18**

#### **विवादों का निपटारा**

1. केन्द्रीय प्राधिकारी इस करार की व्याख्या, इसके लागू होने या कार्यान्वयन से पैदा होने वाले किसी भी विवाद को परस्पर सुलझाने का प्रयास करेंगे।
2. यदि केन्द्रीय प्राधिकारी विवाद को परस्पर सुलझाने में समर्थ नहीं होते हैं तो इसे राजनयिक चैनलों के माध्यम से सुलझाया जाएगा।

### **अनुच्छेद 19**

#### **दण्डित व्यक्तियों को सौंपा जाना**

अन्तरित किए जाने वाले व्यक्ति को अंतरणकर्ता देश द्वारा प्राप्तकर्ता देश को एक ऐसे स्थान पर सौंपा जाएगा जिसके लिए अंतरणकर्ता तथा प्राप्तकर्ता देश के बीच सहमति हो गई हो। प्राप्तकर्ता देश कैदी के अंतरणकर्ता देश से अभिवहन के लिए जिम्मेदार होगा तथा वह अंतरणकर्ता देश के भू-भाग से बाहर दंडित व्यक्ति की हिरासत के लिए भी जिम्मेदार होगा।

**अनुच्छेद 20****संशोधन**

संविदाकार देशों द्वारा सहमत इस करार में कोई संशोधन अथवा आशोधन उसी प्रकार से लागू होगा जैसा कि करार लागू है।

**अनुच्छेद 21****अंतिम प्रावधान**

1. यह करार किसी भी संविदाकार देश की ऐसी लिखित अंतिम अधिसूचना प्राप्त होने के बाद 30वें दिन प्रभावी होगा कि इस करार के प्रभावी होने के लिए उनकी अपनी संवैधानिक अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है।
2. यह करार किसी संविदाकार देश को करार के परिसमापन की लिखित सूचना देकर परिसमाप्त किया जा सकेगा। यह परिसमापन ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से छः माह के बाद प्रभावी होगा।
3. किसी भी परिसमापन के बावजूद, यह करार उन दण्डित व्यक्तियों के दण्डों के प्रवर्तन पर लागू रहेगा जिन्हें इस परिसमापन के प्रभावी होने की तारीख से पहले इस करार के अंतर्गत अंतरित किया गया हो।

इस करार के साक्ष्य के रूप में, अपने संबंधित सरकारों द्वारा इस संबंध में विधिवत रूप से प्राधिकृत किए जाने पर, अधोहस्ताक्षरी ने इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

इसके सभी पाठ समान रूप से अधिप्रमाणित होने के नाते इसे अंकारा में दिनांक को हिन्दी, तुर्की और अंग्रेजी में दो प्रतियों में तैयार किया गया है। व्याख्या में मतभेद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

भारत गणराज्य की ओर से

तुर्की गणराज्य की ओर से

ह./-

ह./-

सुष्मिता गांगुली थॉमस

सादुल्ला एर्गिन

असाधारण राजदूत एवं पूर्णाधिकारी भारत गणराज्य

न्याय मंत्री

[फा. सं. वी-17011/7/2009-पी आर]

एस. सुरेश कुमार, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF HOME AFFAIRS**

(CS Division)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th March, 2014

**G.S.R. 210(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-sections 445(1) and (2) of section 3 of the Repatriation of Prisoners Act, 2003 (49 of 2003), the Central Government having ratified the Agreement on the 27<sup>th</sup> September, 2013, hereby directs that the provisions of the said Act shall apply to the Republic of Turkey and notifies the full text of the treaty entered into between the Government of the Republic of India and the Republic of Turkey for the transfer of prisoners between that country and India as follows, namely :—

**AGREEMENT ON THE TRANSFER OF SENTENCED PERSONS BETWEEN THE REPUBLIC OF INDIA AND THE REPUBLIC OF TURKEY**

The Republic of India and the Republic of Turkey hereinafter referred to as the Contracting States;

Desiring to facilitate the social rehabilitation of sentenced persons into their own countries; and

Considering that this objective should be fulfilled by giving foreign nationals, who have been convicted and sentenced as a result of their commission of a criminal offence, the opportunity to serve their sentences within their own society;

Have agreed as follows:

## **ARTICLE 1**

### **Definitions**

For the purpose of this Agreement:

- (a) "judgment" means a decision or order of a court or tribunal imposing a finalized sentence;
- (b) "receiving State" means a State to which the sentenced person may be, or has been, transferred in order to serve his sentence or remainder thereof;
- (c) "sentence" means any final punishment or measure involving deprivation of liberty ordered by a court or tribunal for a determinate period of time, or for life imprisonment, in the exercise of its criminal jurisdiction;
- (d) "sentenced person" means a person undergoing a sentence of imprisonment under a judgement passed by a criminal court including the courts established under the law for the time being in force in the Contracting States;
- (e) "transferring State" means the State in which the sentence was imposed on the person who may be, or has been transferred.

## **ARTICLE 2**

### **General Principles**

1. A person sentenced in the territory of one Contracting State may be transferred to the territory of the other Contracting State in accordance with the provisions of this Agreement in order to serve the sentence imposed on him. To that end, he may express to the transferring State or the receiving State his willingness to be transferred under this Agreement.
2. Transfer may be requested by any sentenced person who is a national of a Contracting State or by any other person who is entitled to act on his behalf or by his/her legal representative in accordance with the laws of the Contracting State or by making an application to the Contracting State and in the manner prescribed by the laws of the Contracting State.

## **ARTICLE 3**

### **Central Authorities**

1. Authorities in charge of the implementation of this Agreement for the Contracting States are:  
For the Republic of India : the Ministry of Home Affairs;  
For the Republic of Turkey: the Ministry of Justice.
2. In case either Contracting State changes its competent authorities, it shall notify the other Contracting State of the same through official channels.

## **ARTICLE 4**

### **Conditions for Transfer**

1-A sentenced person may be transferred under this Agreement only on the following conditions:

- (a) the person is a national of the receiving State;
- (b) the judgment is final;
- (c) no criminal proceedings are pending against the sentenced person in the transferring State in which his presence is required;
- (d) at the time of receipt of the request for transfer, the sentenced person still has at least six months of the sentence to serve or is undergoing a sentence of life imprisonment;
- (e) that the acts or omissions for which that person was sentenced in the transferring State are those which are punishable as a crime in the receiving State, or would constitute a criminal offence if committed on its territory;

- (f) transfer of custody of the sentenced person to the receiving State shall not be prejudicial to the sovereignty, security or any other essential interest of the transferring State;
- (g) if the transfer is consented to by the sentenced person or, where in view of his/her age or physical or mental condition one of the two Contracting States considers it necessary, by the sentenced persons' legal representative or by any other person who is entitled to act on his/her behalf; and
- (i) the transferring and receiving States agree to the transfer.

2. In exceptional cases, the transferring and receiving States may agree to a transfer even if the remaining period to be served by the sentenced person is less than six months.

## ARTICLE 5

### Obligation to Furnish Information

1. If the sentenced person has expressed an interest to the transferring State in being transferred under this Agreement, the transferring State shall send the following information and documents to the receiving state unless either the receiving or the transferring State has already decided that it will not agree to the transfer:

- (a) the name and nationality, date and place of birth of the sentenced person and his address, if any, in the receiving State along with a copy of his passport or any other personal identification documents, and fingerprints of the sentenced person, as possible;
- (b) a statement of the facts upon which the sentence was based;
- (c) the nature, duration and date of commencement of the sentence;
- (d) a certified copy of the judgment and a copy of the relevant provisions of the law under which the sentence has been passed against the sentenced person;
- (e) a medical, social or any other report on the sentenced person, where it is relevant for the disposal of his application or for deciding the nature of his confinement;
- (f) any other information which the transferring State may specify as required to enable it to consider the possibility of transfer and to enable it to inform the sentenced person of the full consequences of transfer for him/her under its law;
- (g) the request of the sentenced person to be transferred or of a person entitled to act on his/her behalf in accordance with the law of the transferring State or of the sentenced person's legal representative;
- (h) a statement indicating how much of the sentence has already been served, including information on any pre-trial detention, remission, or any other factor relevant to the enforcement of the sentence, and
- (i) After furnishing of the requisite information, a statement from the transferring State agreeing to the transfer of the Sentenced Person shall be provided to the receiving State.

2. For the purposes of enabling a decision to be made on a request under this Agreement, the receiving State shall send the following information and documents to the transferring State unless either the receiving or the transferring State has already decided that it will not agree to the transfer:

- (a) a statement or document indicating that the sentenced person is a national of the receiving State;
- (b) a copy of the relevant law of the receiving State which provides that the acts or omissions on account of which the sentence has been imposed in the transferring State constitute a criminal offence according to the law of the receiving State, or would constitute a criminal offence if committed on its territory;
- (c) a statement of the effect of any law or regulation relating to the duration and enforcement of the sentence in the receiving State after the sentenced person's transfer including, if applicable, a statement of the effect of paragraph 2 of Article 9 of this Agreement on his transfer;
- (d) the willingness of the receiving State to accept the transfer of the sentenced person and an undertaking to administer the remaining part of the sentence of the sentenced person; and
- (e) any other information or document which the transferring State may consider necessary.

**ARTICLE 6****Requests and Replies**

1. Requests for transfer shall be made in writing by the central authority of the transferring State through diplomatic channels to the central authority of the receiving State. Replies shall be communicated through the same channels.
2. The receiving State shall promptly inform the transferring State of its decision whether or not to agree to the requested transfer.

**ARTICLE 7****Consent and its Verification**

1. The transferring State shall ensure that the person required to give consent to the transfer in accordance with paragraph 1 (g) of Article 4 of this Agreement, does so voluntarily and with full knowledge of the legal consequences thereof. The procedure for giving such consent shall be governed by the law of the transferring State.
2. The transferring State shall afford an opportunity to the receiving State to verify through a consul or other official appointed in compliance with the law of the receiving State, that the consent is given in accordance with the conditions set out in paragraph 1 of this Article.

**ARTICLE 8****Effect of Transfer for the Receiving State**

1. The competent authorities of the receiving State shall continue the enforcement of the sentence through a court or administrative order, as may be required under its national law, under the conditions set out in Article 9 of this Agreement.
2. Subject to the provisions of Article 11 of this Agreement, the enforcement of the sentence shall be governed by the law of the receiving State and that State alone shall be competent to take all appropriate decisions.

**ARTICLE 9****Continued Enforcement of Sentence**

1. The receiving State shall be bound by the legal nature and duration of the sentence as determined by the transferring State.
2. If the sentence is by its nature or duration, or both, incompatible with the law of the receiving State, that State may, with the prior consent of the transferring State, by court or administrative order, adapt the sentence to a punishment or measure prescribed by its own law. As to its nature and duration the punishment or measure shall, as far as possible, correspond with that imposed by the judgment of the transferring State. It shall however not aggravate, by its nature or duration, the sentence imposed by the transferring State.

**ARTICLE 10****Effect of Completion of Sentence for the Transferring State**

When the receiving State notifies the transferring State under paragraph 1(a) of Article 13 of this Agreement that the sentence has been completed, such notification shall have the effect of discharging that sentence in the transferring State.

**ARTICLE 11****Review of Judgement and Pardon, Amnesty or Commutation of Sentence**

1. The transferring State alone shall have the right to decide on any application for the review of the judgement.
2. Either of the Contracting States may grant pardon, amnesty or commutation of the sentence in accordance with its Constitution or other laws.

**ARTICLE 12****Termination of Enforcement of Sentence**

1. The transferring State shall promptly notify the receiving State of any decisions taken in its territory which entails terminating the enforcement of the sentence or part thereof.

2. The receiving State shall terminate enforcement of the sentence or part thereof as soon as it is informed by the transferring State of any decision or measure as a result of which the sentence ceases to be enforceable.

### **ARTICLE 13**

#### **Information on Enforcement of Sentence**

1. The receiving State shall notify the transferring State:
  - (a) when the enforcement of the sentence has been completed; or
  - (b) If the sentenced person escapes from custody before enforcement of the sentence has been completed, in such cases, the receiving State shall take measures to secure his arrest for the purposes of serving the remainder of his sentence and to render him/her liable for committing an offence under the relevant laws of the receiving State.
2. The receiving State shall furnish a special report concerning the enforcement of the sentence, if so required by the transferring State.

### **ARTICLE 14**

#### **Transit**

1. If either Contracting State enters into arrangements for the transfer of sentenced persons with any third State, the other Contracting State shall cooperate in facilitating the transit through its territory of the sentenced persons being transferred pursuant to such arrangements, except that it may refuse to grant transit;
  - (a) if the sentenced person is one of its own nationals, or,
  - (b) if the request may infringe upon the sovereignty, safety, public order or any other essential interest of the Contracting State.
2. The Contracting State intending to make such a transfer shall give advance notice to the other Contracting State of such transit.

### **ARTICLE 15**

#### **Costs**

Any costs incurred in the application of this Agreement shall be borne by the receiving State, except costs incurred exclusively in the territory of the transferring State. The receiving State may, however, demand or seek to recover all or part of the costs of transfer from the sentenced person or from some other source.

### **ARTICLE 16**

#### **Language**

Requests and supporting documents shall be in the official language of each Contracting State and shall be accompanied by an English translation.

### **ARTICLE 17**

#### **Scope of Application**

This Agreement shall be applicable to the enforcement of sentences imposed either before or after the entry into force of this Agreement.

### **ARTICLE 18**

#### **Settlement of Disputes**

1. The Central Authorities shall endeavour to mutually resolve any dispute arising out of the interpretation, application or implementation of this Agreement.
2. If the Central Authorities are unable to resolve the dispute mutually, it shall be resolved through diplomatic channels.

**ARTICLE 19****Handing Over of Sentenced Persons**

The handing over of the transferred person by the transferring State to the receiving State shall occur at a place to be agreed upon between the transferring and receiving State. The receiving State shall be responsible for the transport of the prisoner from the transferring State and shall also be responsible for custody of the sentenced person outside the territory of the transferring State.

**ARTICLE 20****Amendments**

Any amendments or modifications to this Agreement agreed to by the Contracting States shall come into force in the same manner as the Agreement itself.

**ARTICLE 21****Final provisions**

1. This Agreement shall enter into force on the 30<sup>th</sup> day after the last notification of either of the Contracting States in writing is received that their respective constitutional requirements for entry into force of this Agreement have been complied with.
2. Each Contracting State may terminate this Agreement by giving a written notice of termination to the other Contracting State. The termination shall take effect after six months of the date of receipt of such notice.
3. Notwithstanding any termination, this Agreement shall continue to apply to the enforcement of sentences of sentenced persons who have been transferred under this Agreement before the date on which such termination takes effect.

In witness whereof the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done in duplicate at Ankara on the 30th day of October, 2012, in the Hindi, Turkish and English languages, all texts being equally authentic. In case of differences in interpretation, the English text shall prevail.

**FOR  
THE REPUBLIC OF INDIA  
Sd/-**

**SUSMITA GONGULEE THOMAS  
AMBASSADOR EXTRAORDINARY AND  
PLENIPOTENTIARY OF THE  
REPUBLIC OF INDIA**

**FOR THE  
REPUBLIC OF TURKEY  
Sd/-**

**SADULLAH ERGIN  
THE MINISTER OF JUSTICE**

[F. No. V-17011/7/2009-PR]  
S. SURESH KUMAR, Jt. Secy.